

## थम विभाग

आदेश

दिनांक 7 दिसम्बर, 1983

सं. ओ.वि./करनाल/36-83/63821.—चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राय है कि कार्यकारी अधिकारी रेट महंनर ईरीगेशन ट्यूबबैल कार्यपालन ट्यूबबैल विदिजन नं. ०१, भल रोड, करनाल, के श्रमिक श्री करण सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के स्वरूप में कोई श्रीदोगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, श्रीदोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (१) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ७के अधीन श्रीदोगिक अधिकारण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री करण सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ.वि./एफ.डी./287-83/63827.—चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राय है कि मैं ओसवाल इन्हींनियरिंग एण्ड जनरल वर्क्स, 48 एन.आई.टी. फरीदाबाद, के श्रमिक श्री नरेन्द्र मोहन तथा उसके प्रबन्धकों के माध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई श्रीदोगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, श्रीदोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (१) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ७के अधीन श्रीदोगिक अधिकारण, हरियाणा फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री नरेन्द्र मोहन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ.वि./जी.जी.एन./132-८३/63835.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं चन्द्र नगर के भीकल्ज एण्ड मिनरल प्रा. ०५० चन्द्र नगर, गुडगांव, के श्रमिक श्री शश्मु नाथ तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीदोगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करता बांछनीय समझते हैं;

इस लिये, अब, श्रीदोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (१) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. ५४१५-३-श्रम-६४/१५२५४, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पंदरे हुए अधिसूचना सं. ११४९५-जी-श्रम-५७/११२४५, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ७ के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री शश्मु नाथ की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं.ओ.वि./भिवानी/198-८३/63842.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं मोडल एक्सोटिक एनिमल कार्म, भिवानी (ii) हरियाणा डेरी टि-पै-पै-टोपरेटिव फैडरेशन लि० चण्डीगढ़, के श्रमिक श्री शारसी दास तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीदोगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबन्धित मामला है:—

क्या श्री बनारसी दास की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./रोहतक/223-83/63849.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं इन्टरनैशनल पार्सिप वर्क्स दिल्ली रोहतक रोड, जाखोदा (बहादुरगढ़) के श्रमिक श्री हंस राज विश्वकर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6-11-1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8-5-70 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबन्धित मामला है:—

क्या श्री हंस राज विश्वकर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./रोहतक/222-83/63856.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, की राय है कि मैं हिन्दुस्तान पोटरीज इन्डस्ट्रीज बहादुरगढ़ (रोहतक) के श्रमिक श्री भगवान सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई)-श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबन्धित मामला है:—

क्या श्री भगवान सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./अम्बाला/83-83/63863.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं निदेश व पद्धिम हैत्यक्षसंविस हरियाणा चण्डीगढ़, के श्रमिक श्री बाल राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद/लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री बाल राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?